

MVS/UB/10

15-11-99

हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही

8 फरवरी, 1999
खण्ड 1 अंक - 8
अधिकृत विवरण



विषय-सूची

सोमवार, 8 फरवरी, 1999

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
राज्यपाल से सन्देश	(8)17
बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश करना	(8)17
वर्ष 1999-2000 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरागम)	(8)19
विल्ल—	
(i) दि पंजाब विलेज कॉमन लेण्डिज (रेगुलेशन) हरियाणा अमेंडमेंट बिल, 1999	(8)25
(ii) दि हरियाणा लोकपाल (अमेंडमेंट) बिल, 1999	(8)27
(iii) दि पंजाब ऐक्साइज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1999	(8)28
(iv) दि पंजाब वेयरहाउसिंग (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1999	(8)29
(v) गुरु जम्भेश्वर यूनीवर्सिटी, हिसार (अमेंडमेंट) बिल, 1999	(8)31

मूल्य :

55

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 8 फरवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर - 1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मੈम्बर, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-814

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री देवराज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या-940

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री रामफल कुण्डू सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Providing of Service Lane

*859. Shri Anil Vij : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state —

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government, to construct service lanes on either side of the Ambala-Jagadhri State highway from Civil Hospital to Mahesh Nagar at Ambala Cantt.; and
- (b) if so, the time by which aforesaid service lane is likely to be constructed ?

सड़क निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह बलाल) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने हाउस में बताना चाहूंगा कि अम्बाला-जगाधरी रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है और यह रोड शहर के बीचों बीच में से हो कर जाता है तथा सिविल अस्पताल से ले कर महेश नगर तक इस सड़क के दोनों ओर कई एजुकेशनल और दूसरे इंस्टीच्यूट्स हैं, जैसे क्वाइंड इंस्टीच्यूट है, एस०डी० कॉलेज है, डी०ए०वी० कॉलेज है कुछ स्कूल भी हैं दूसरे शब्दों में कहा जाये तो यह एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। इस रोड पर हर रोज़ अनेकों दुर्घटनाएँ होती

[श्री अनिल विज]

हैं, मैंने इस बारे में पहले भी सवाल पूछा था कि क्या इस पर कोई बाई पास बनाने का प्रस्ताव है तो उसका जवाब 'नहीं' में मिला था। मैंने अपने सवाल में यह कहा था कि इस रोड से कोई बाई पास बना कर सीधे टांगरी तक रोड निकाला जाए तो उसका जवाब 'नहीं' में मिला था और आज इस पूछे गये प्रश्न का जवाब भी 'नहीं' में मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए यहाँ पर पी०डब्ल्यू०डी० क्या कारगर कदम उठाने जा रही है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस सर्विस लाईनिंग की बात माननीय साथी अनिल विज जी कर रहे हैं, इस बारे में मैं इन को बताना चाहूंगा जैसे आपको भी पता है इस समय हरियाणा में जो सड़कें हैं उनकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है इसलिए हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश है कि पहले हम प्रदेश में उन तमाम दूदी हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवा लें और उसके बाद प्रदेश में जो अन्य काम हैं, वे करवाए जाएं। जैसे अनिल विज जी ने सर्विस लाईन के बारे में पूछा है उसके लिए 29-30 लाख रुपये लगने की सम्भावना है इसलिए इस वर्ष या अगले वर्ष तक यह सर्विस लेन बनाने का कोई विचार नहीं है। जहां तक इनका यह कहना है कि यहाँ पर एक्सिडेंट्स का डर रहता है उसके लिए सेंटर वर्ज जो कि सड़क को बीच से विभाजित करता है और सेंटर वर्ज की विज साइब की मांग भी है, उसके बारे में हम विचार करेंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि अभी सड़कों की मरम्मत के लिए काफी काम किया जा रहा है और मैंने जिस सड़क के बारे में प्रश्न किया था उसके बारे में मंत्री जी ने बताया कि सेंटर वर्ज बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह सेंटर वर्ज बनाने का विचार ही किया जा रहा है या सेंटर वर्ज बनाने का निर्णय डिपार्टमेंट ने ले लिया है ? यदि इसको बनाने का निर्णय ले लिया गया है तो कब तक यह बन जाएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री अनिल विज जी को बताना चाहूंगा कि सेंटर वर्ज पर भी हम अभी विचार ही कर रहे हैं और यह विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई शहरों में हमने अनुभव किया है कि सेंटर वर्ज ट्रैफिक को समूची चलने में उल्टा फ्लो साबित होता है इस समस्या के चलते कई शहरों में सेंटर वर्ज जो बन हुए थे, उनको उखाड़ना पड़ा है। सेंटर वर्ज बना कर भी शायद इनकी समस्या समाप्त नहीं होगी। इसलिए मैंने अभी डिपार्टमेंट को यह कहा है कि वे इस बात को देखें कि सेंटर वर्ज ट्रैफिक को समूची चलाने में कितना लाभदायक होता है। इस बारे में निर्णय ले जाने के बाद ही इसको बनवाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से अन्तिम प्रश्न यह है कि ये सर्विस लेन भी नहीं बनवा रहे हैं, बाई-पास और सेंटर वर्ज भी अभी नहीं बनवा रहे हैं तो क्या मंत्री जी सेंटर कार्रपोटिंग के लिए कुछ विचार कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही ये अम्बाला रेलवे स्टेशन से टांगरी ब्रिज तक सड़क रिपेयर करने के बारे में भी बताएं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि मौसम हमारा साथ देता तो हम शायद इसको ठीक भी करवा देते। पिछले महीनों में बारिश होती रही और ठंड भी काफी रही जिस ब्रिज से इसका काम नहीं हो पाया था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की मरम्मत का सवाल है, सड़कों की मरम्मत अवश्य करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनका एक प्रश्न यहाँ पर नहीं लग पाया था। हम साक्षात्

शाहबाद तक सड़क बनवा रहे हैं उससे हाई-वे पर पंजाब से जो हेवी ट्रैफिक आता है, उसका रश निश्चित तौर पर कम हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, भिवानी जिले में 1995 में जो बाढ़ आई उस बाढ़ से खासकर भिवानी की सड़कें जो गांवों में जाती है वे बुरी तरह से टूट गई थीं, तहस-नहस हो गई थी, उनको आप उदारता दिखाते हुए कब तक रिपेयर करवा देंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग ने एक कार्यक्रम बनाया है कि राज्य में जितनी भी सड़कें हैं पहले वे रिपेयर करवायी हैं। अध्यक्ष महोदय, जितने भी स्टेट हाई-वे हैं, वे चाहे कहीं भी हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाएंगे। एम०डी०आर० भी हम ठीक करने जा रहे हैं। ये जो विलेज लिंक रोड्स हैं जो बाढ़ आने की वजह से बुरी तरह टूट गई थी चाहे वे भिवानी, रोहतक, जीन्द या कैथल में हों, उनकी रिपेयर की मुख्यमंत्री जी से इजाजत लेकर आने वाले मार्च में उन्हें ठीक करवाने के बारे में विचार करेंगे। अभी हमारा स्टेट हाई-वे, एम०डी०आर० और पांच सौ किलोमीटर ओ०डी०आर० का काम करने का विचार है।

श्री जोग प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने भिवानी जिले के बारे में विश्वास दिलाया है कि जितनी भी रोड्स हैं वे रिपेयर हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं जब अपनी कांस्टीचूएंसि में जाता हूँ तो मुझे अपनी पैंट उपर करके जाना पड़ता है क्योंकि वहां की सड़कें टूटी पड़ी हैं और उन सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। वहां पर चार-पांच सड़कें जैसे जाटन, औटनी इत्यादि हैं वथा मंत्री जी उनको भी ठीक करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जैन साहब को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी जो विलेज लिंक रोड्स के बारे में बताया है वह केवल भिवानी जिले के बारे में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बारे में बताया है। हम एम०डी०आर और 500 कि०मी० ओ०डी०आर० को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिस गांव का नाम लिया है मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमने विलेज लिंक रोड्स को ठीक करने का काम अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि पैसे की बहुत भारी कमी है साथ ही मौसम भी हमारा इस मामले में बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है कभी बारिश आ जाती है कभी कुछ और हो जाता है। स्पीकर सर, आने वाले मार्च के बाद हम गांवों की लिंक रोड्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : स्पीकर सर, जिन गांवों की रोड्स बिल्कुल खराब हो चुकी हैं और जहां पर लोगों को गन्ना ले जाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वहां की लिंक रोड्स को क्या मंत्री जी प्रायोरिटी बेसिस पर बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि शुगर मिल्स में गन्ना देना तो टाईम बाउंड होता है और मार्च के बाद तो गन्ने का सीजन खल सा हो जाएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, माननीय बिजेन्द्र सिंह कादयान जी ने ठीक ही कहा है इसलिए हमारे विभाग ने गन्ने का सीजन शुरू होने से पहले ही कॉर्पोरेटिव शुगर मिल्स एवं प्राइवेट शुगर मिल्स के एम०डी०आर की एक मीटिंग बुलाई। हमने इस बारे में इन एम०डी०आर को भी व हर जिले के डी०सी०आर को भी कहा है। जहां जहां पर भी शुगर मिल्स हैं वहां के गांवों की लिंक रोड्स की इमन प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने की कोशिश की है फिर भी अगर इनके इलाके की कोई इस तरह की रोड जो शुगर मिल को जाती है, वह ठीक नहीं हुई है तो उसके बारे में ये मुझे बताने दें हम उसको ठीक कर देंगे।

Opening of Government College for Women at Charkhi Dadri

*970. Shri Sat Pal Sangwan : Will the Minister for Education be pleased to state —

- (a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College for Women at Bhiwani, and Charkhi Dadri;
- (b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) :

- (क) जी नहीं।
- (ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, पता नहीं शिक्षा मंत्री जी हमारे से इतना खुश क्यों रहते हैं कि हर सवाल का जवाब 'न' में ही देते हैं क्योंकि इन पौने तीन साल में मैंने यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके जवाब में इन्होंने 'न' ही की है। ये तो उस इलाके से गुजरते रहते हैं इसलिए कभी तो इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। दादरी और भिवानी के एरिया में ज्यादातर मिलिट्री के सर्विस वाले लोग रहते हैं और इनके बच्चे इनके साथ जा नहीं सकते इसलिए उनकी लड़कियों को स्कूल आने जाने में बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है वहां पर कोई भी राजकीय महिला कालेज नहीं है तो क्या मंत्री जी इस बारे में दोबारा सोचेंगे ?

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब ने यह जानना चाहा है कि इस सभ्य चरखी दादरी में कोई राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है तो क्या वहां पर यह महाविद्यालय खोला जाएगा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि भिवानी जिले में इस समय 12 महाविद्यालय चल रहे हैं जिनमें से 5 महाविद्यालय राजकीय और 7 महाविद्यालय ऐसे हैं जो सरकारी नहीं हैं बल्कि जिनको प्राइवेट संस्थाएं चलाती हैं। दादरी में ही तीन महाविद्यालय इस समय चल रहे हैं। भिवानी जिले में 5 राजकीय महाविद्यालय इस तरह से हैं— राजकीय महाविद्यालय, भिवानी, राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी, राजकीय महाविद्यालय, लोहारू, राजकीय महाविद्यालय, चौदकलां, राजकीय महाविद्यालय, सिवानी और गैर सरकारी महाविद्यालय इस तरह से हैं— वैश्य कालेज, भिवानी, आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी, के० एम० शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी, जे०वी०एम०जी०आर०आर० कालेज चरखी दादरी, ए०पी०जे०सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी, सरस्वती शिक्षण महाविद्यालय चरखी दादरी, वी० एल० जे० सुईवाला, लौशांम। फिर भी यदि विद्यार्थक साहब वहां पर और राजकीय महिला कालेज की आवश्यकता महसूस करते हैं तो हमें ये वहां पर कोई जगह दे दें या भवन के बारे में बताएं इसके बाद वहां पर राजकीय महिला महाविद्यालय बनाने के बारे में हम विचार करेंगे ?

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, विल्डिंग बनवाने के लिए तो हमारे हल्के के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, हां जगह जरूर दिला देंगे।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब से तो मेरी बहुत हमदर्दी है मैं अपनी स्कूल एजुकेशन के समय छठवीं व सातवीं क्लास में इनके हल्के में भाग्यी में पढ़ता रहा। उस विद्यालय और वहां की शिक्षा के बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जमीन जिसमें दिलाएंगे उससे हम भवन के बारे में भी बात करेंगे।

श्री सतपाल सांगवान : भागवी में आप पढ़े हैं वहां के मिडिल स्कूल को हाई में बदलने की तो हों भर दें।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भागवी के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को हम अगले सत्र में गर्ल्स हाई स्कूल में अपग्रेड करेंगे और जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसको पहले ही अपग्रेड करके हाई का दर्जा दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी, कालेजों की संख्या का सवाल है वह पोजीशन तो आपकी उंगलियों पर है लेकिन भिवानी का जहां तक संबंध है भिवानी में दस गर्ल्स कालेज हैं लेकिन दाखिले के समय वहां आम लड़कियों को दाखिला मिलना मुश्किल हो जाता है दाखिला न मिल पाने की वजह से भिवानी की कुछ लड़कियाँ दादरी जाकर दाखिला लेने को मजबूर हो जाती हैं क्योंकि वहां एक कालेज है और किसी एक आदमी की वहां मोनोपली है। वास्तव में दादरी और भिवानी दो ऐसे स्थान हैं जहां कालेज तो हैं लेकिन गवर्नमेंट के कालेज ज्यादा नहीं हैं। भिवानी और दादरी दोनों ही और विशेष रूप से भिवानी एक ऐसी जगह है जहां गवर्नमेंट के और विशेषतः वीमेन कालेज की बड़ी आवश्यकता है। क्या आप कोई आश्वासन देंगे जिससे कालेज की स्थापना वहां शीघ्र हो सके ?

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपका तो आदेश है हम आपके आदेश की पालना करेंगे। जैसे बौद में आपने भवन बनवाकर दिया। दादरी के लिए सतपाल सांगवान जी का यह कहना ठीक नहीं है कि वहां पैसे वाले नहीं हैं सेठ नहीं हैं। रासीवासिया एक परिवार ने एक महाविद्यालय के लिए भवन बना के दिया। सतपाल सांगवान जी जमीन उपलब्ध करवाएँ, भवन बनवाकर दें, हम जरूर विचार करेंगे।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भिवानी के अंदर दादरी और मेहम रोड पर स्थित विद्या नगर कालोनी में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जबकि वहां आबादी बहुत ज्यादा है क्या मंत्री जी वहां प्राइमरी स्कूल बनाने बारे आश्वासन देंगे ?

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां भी 50 बच्चे उपलब्ध होते हैं हम वहां प्रांच स्कूल खोल देते हैं। सोमवीर जी, आप इस बारे में लिखकर दे दें हम विद्या नगर कॉलोनी, भिवानी में भी प्रांच स्कूल खोल देंगे।

श्री जगदीश नेयर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भेरा हसनपुर ऐसा इलाका है कि वहां न तो लड़कों की और न ही लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था है। यदि हसनपुर में एक महाविद्यालय खोलने का प्रबन्ध किया जाए तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, जगदीश नेयर जी का वृज का इलाका है वहां तीन करोड़ रुपये की 15 एकड़ जमीन है उस बारे वहां के लोगों की कोई कमेटी बनाकर उस पर भवन बनवा दें तो आपके हसनपुर में भी कॉलेज खोलने के लिए विचार किया जा सकता है। आप इस बारे में हम से विचार विमर्श करें।

श्री जगदीश नेयर : ठीक है जी।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसराना में कालेज की इमारत बन कर तैयार हो चुकी है क्या अगले सत्र से वहाँ कक्षाएँ आरम्भ करने पर विचार करेंगे क्योंकि यह आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ पर एक जनसभा में दिया था।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने सही फर्माया है, वहां पर स्थानीय लोगों की एक संस्था बनाकर उनका सहयोग लेकर कालेज के लिए भवन बनाया गया है और मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के मुताबिक अगले सत्र से वहां पर कक्षाएँ आरम्भ कर दी जाएंगी।

तारांकित प्रश्न संख्या -920

(इस समय माननीय सदस्य श्री नरेंद्र सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न संख्या -901

(इस समय माननीय सदस्य श्री वलवीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न संख्या -931

(इस समय माननीय सदस्य श्री रमेश कुमार खटक सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

तारांकित प्रश्न संख्या -951

(इस समय माननीय सदस्य राव नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

Tubewells out of order

***972. Shri Om Parkash Jain :** Will the Minister for Public Health be pleased to state —

(a) Whether it is a fact that the tubewells of the following Colonies of Panipat are not functioning :-

- (i) Virat Nagar;
- (ii) Ekta Vihar;
- (iii) Ugra Kheri;
- (iv) Krishan Pura;
- (v) New Model Town;
- (vi) Ashok Vihar (Noorwala);
- (vii) New Ramesh Nagar (Bichhpuri);
- (viii) Gita Colony (Noorwala);
- (ix) Rajiv Colony (Ward No. 10);
- (x) Batra Colony (Ward No. 1); and

- (b) if so, the reasons thereof together with the time by which these are likely to be made functional ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) :-

(क) केवल 5 कालोनियां विराट नगर, कृष्णपुरा, नया माडल टाऊन, राजीव कालोनी और वतरा कालोनी पानीपत शहर के भाग हैं। सभी 5 नलकूप जोकि इन कालोनियों के लिए लगाए गये थे नये नलकूप हैं जिनमें से राजीव कालोनी का एक नलकूप 9/98 में चालू कर दिया गया था। बाकी 4 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है।

अन्य 5 कालोनियां एकता विहार, उग्रा खेड़ी, अशोक विहार, नया रमेश नगर तथा गीता कालोनी ग्रामीण क्षेत्र का भाग है। उग्रा खेड़ी का नलकूप 9/95 से कार्य कर रहा है। बाकी अन्य 4 नलकूप नये नलकूप हैं जिनमें से गीता कालोनी का एक नलकूप 11/98 में चालू कर दिया गया है। अन्य 3 नलकूपों पर कार्य प्रगति पर है।

(ख) शेष 7 नलकूपों का कार्य पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होने पर दिसम्बर, 1999 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर तो अभी नल ही खड़े हैं इसके अलावा न तो वहाँ कोई मशीन लगी है और न ही कोई कनेक्शन दिया गया है। राजीव कालोनी में तो एक नल चालू है और कृष्णपुरा में दो नलकूप जो एम०पी० कोटे से लगाये गये थे, उनको चालू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है दूसरा माँडल टाऊन के नलकूपों की अभी तक सिक्वोरिटी भी जमा नहीं की गई है। जब महकमें से इस बारे में पूछा जाता है तो वे कह देते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है। उस इलाके में चार नलकूप हैं जिनमें से एक ही नलकूप चालू है। राजीव कालोनी में तो ट्यूबवैल को अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। विभाग से जब इस बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि म्युनिसिपल कमिटी से एन०ओ०सी० लाओ। म्युनिसिपल कमिटी वाले एन०ओ०सी० देते नहीं। ये कालोनियाँ 15-20 साल से पहले की बनी हुई हैं। वहाँ के लोग इस बारे में पैसा देने के लिए तैयार हैं वे कहते हैं कि अगर एन०ओ०सी० मिल जाता तो है हमें 400/- रुपये भरने पड़ेंगे एन०ओ०सी० नहीं मिलती तो हमें 1500/- रुपये भरने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, वहाँ की कमिटी हमारा कोई काम नहीं करती है वल्कि वह हमारे यहाँ के गरीब आदमियों को सताती है, इसलिए उस कमिटी को बनाने का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कमिटी को ऐसे आदेश दिए जाने चाहिए कि यदि कोई आदमी सारी कागजी कार्यवाही पूर्ण कर दे तथा फीस बगैरह भी जमा करवा दे तो उसको तुरंत ही कनेक्शन मिल जाना चाहिए। इसके अलावा चार इलाके ऐसे हैं, जहाँ पर कनेक्शन लेने के लिए अभी तक कोई सिक्वोरिटी नहीं भरी गई है। शहर से बाहर के इलाकों की जहाँ तक बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि अशोक विहार में तो चुनावों से पूर्व ही ट्यूबवैल लगा हुआ है, वहाँ पर मशीन पहले से ही लगी पड़ी है, लेकिन उसके कनेक्शन के लिए अभी तक कोई सिक्वोरिटी नहीं भरी गई है। मुख्य खर्चा तो ट्यूबवैल लगाने का ही होता है। इसलिए जहाँ पर पहले से ही ट्यूबवैल बगैरह लगे हुए हैं, उनकी सिक्वोरिटी जो कि मात्र 10 या 12 हजार रुपये ही होती है, वह सिक्वोरिटी भरवाकर कनेक्शन दिलवाए जाएं ताकि हमें लाभ मिल सके।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि कृष्णपुरा में तो 3 ट्यूबवैल पहले से ही लगे हुए हैं और वहाँ पर काम 4/97 से शुरू हो गया था, राजीव कालोनी में ट्यूबवैल द्वारा पानी देने का कार्य शुरू कर दिया गया था लेकिन वहाँ पर 200 के गरीब

[श्री जगन नाथ]

अनअथोराईज्ड कनेक्शन होने के बाद वह बंद कर दिया गया है क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो पानी आगे नहीं जाना था। इसलिए वहां की म्यूनिसिपल कमेटी को कहा गया है कि कनेक्शन लेने वाले लोगों के मकानों के नक्शे हमें बनाकर दे दो, उसके बाद हम कनेक्शन दे देंगे। बिगट नगर में 7/98 से काम शुरू हो गया है, नया मॉडल टाउन में कार्य 1/98 से शुरू हो गया है, बतारा कालोनी में 4/98 से काम शुरू हो गया है। शहर के क्षेत्रों के बारे में जो स्थिति थी वह मैं बता चुका हूँ तथा यहाँ पर नगरपालिका के हिसाब से कार्य हो रहा है। मैं यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि पैसे का अभाव रहता है, इसलिए जैसे-जैसे पैसा आएगा, वैसे-वैसे हम काम करते रहेंगे और दिसंबर, 1999 तक यह काम पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र की जो अनअथोराईज्ड कॉलोनियाँ हैं, उन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उग्रा खेड़ी में तो पहले से ही काम चल रहा है, एकता विहार में भी 5/97 से काम चालू है लेकिन काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। नए रमेश नगर तथा अशोक बिहार में भी 4/96 से काम चल रहा है। गीता कॉलोनी में काम पहले से ही चालू था तथा वहाँ पर पानी की सप्लाई भी शुरू हो गई है। लेकिन मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि पैसे का आभतीर पर अभाव रहता है इसलिए हम यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि यह काम इतने समय के अंदर हो जाएगा। हाँ, जैसे-जैसे हमें पैसा मिलता जाएगा वैसे-वैसे हम काम करते रहेंगे।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूँगा कि राजीव कॉलोनी, पानीपत शहर की अथोराईज्ड कॉलोनी है, वहाँ पर सीधे ही जन-स्वास्थ्य विभाग वालों को पैसा जमा करवाकर कनेक्शन नहीं दिया जाता है, इसके लिए पहले कमेटी से एन०ओ०सी० लेनी पड़ती है तथा वहाँ पर कमेटी वालों ने काम नहीं करने की कसम खा रखी है। इस प्रकार गरीब आदमी को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। उस कमेटी में विपक्ष का चेयरमैन है, जिस ने मौजूदा सरकार के समय में कोई काम नहीं करने की कसम खा रखी है। मैं अर्ज करूँगा कि जन स्वास्थ्य विभाग पहले भी सीधे ही कनेक्शन देता रहा है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि यह विभाग सीधे ही उपभोक्ता से 400/- रुपये या जितने रुपए लेने हों, वह लेकर के उनकी रसीद काटकर उन को दे दें तथा सीधे ही उनकी कनेक्शन दे दें अर्थात् बीच में कमेटी का चक्कर ही खत्म हो जाए, ऐसे आदेश यदि जारी कर दिए जाएंगे तो बहुत ही लाभ होगा।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, कमेटी वाले डिवलपमेंटल चार्जिज लेते हैं तथा हमारे पास वे पैसा जमा करवाते हैं। स्थानीय शासन मंत्री महोदय भी यहीं सदन में बैठे हैं, इस संबंध में वे भी अपना जवाब सदन में देंगे। लेकिन मैं तो यही आश्वासन दे सकता हूँ कि जब उपभोक्ता कमेटी वालों के पास पैसा जमा करवा देगा तो हम तुरंत उस को कनेक्शन दे देंगे।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, कनेक्शन के मामले में यदि कमेटी बीच में न आए तो ठीक रहेगा। सीधे ही जन स्वास्थ्य विभाग को पैसे जमा करा दिए जाएँ तो अनावश्यक असुविधा बच जाएगी।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, पैसे जमा करवाने के बाद हम उपभोक्ता को कनेक्शन दे देंगे।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में एक वाटर वर्क्स लगा हुआ है और उसी वाटर वर्क्स से कई गांवों में पानी की सप्लाई होती है। वाटर वर्क्स से दूसरे गांवों में पानी की सप्लाई लाईनें बिछाकर की जाती है। लेकिन कई

जगह पर वे लाइनें टूटी हुई हैं और इस बारे में जब हम आपके अधिकारियों से बात करते हैं तो वे अधिकारी कभी तो कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं और कभी कह देते हैं कि हमें इस बारे में मालूम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गवालड़ा गांव में भी ऐसी ही दिक्कत है। वहां गाँव नाभुंजा के वाटर वर्क्स द्वारा पानी की सप्लाई होती है वह लाइन जोहड़ के नजदीक से गुजरती है और वह लाइन इस समय खराब है। इस बारे में जब अधिकारियों को कहा गया तो अधिकारी कहते हैं कि यह लाइन जोहड़ का पानी सूखने के बाद ही ठीक की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि यह लाइन खराब होने के कारण उस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मेरा मंत्री महोदय, से अनुरोध है कि गवालड़ा गांव की लाइन को जल्दी से जल्दी ठीक करवायें।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से हमारे पास पाइप नहीं थे जिसके कारण जो लाइनें टूटी हुई थी वे ठीक नहीं हो पाई। लेकिन अब आने वाले 15-20 दिन में हमारे पास पाइप आ जायेंगे और मेरे भाई कादयान ने जो लाइन बताई है उसको भी ठीक करवा देंगे।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि इनके अधिकारी कह रहे थे कि जब तक जोहड़ का पानी नहीं सूखेगा तब तक यह लाइन ठीक नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उस जोहड़ का पानी नहीं सूखा तो क्या होगा ?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, अगर उस जोहड़ का पानी नहीं सूखा तो हम लाइन किसी दूसरी साईड से ले लेंगे और उस गांव की पानी की समस्या दूर कर देंगे।

तारकित प्रश्न संख्या -977

(इस समय माननीय सदस्य श्री बन्ता राम सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

Draining Out of Flood Water

*982. **Shri Kapoor Chand Sharma** : Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state ---

- whether it is a fact that there are some villages of Shahabad constituency which remain effected by flood every year and on account of which the great loss is caused to crops; and
- if the reply to para(a) above be in affirmative, whether the Government has formulated any scheme to find out a permanent solution to the said problem togetherwith the time by which the aforesaid scheme is likely to be implemented ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

- शाहबाद निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में बाढ़ की समस्या नहीं है। फिर भी, भारी वर्षा के दौरान फसलों, बाढ़ के पानी के उतरने की अल्प अवधि तक, प्रभावित होती हैं।
- स्थिति में अग्रिम सुधार के लिए तीन योजनाएं अभी-अभी स्वीकृत की जा चुकी हैं। धन की उपलब्धता होने की स्थिति में यह योजनाएं क्रियान्वित होंगी।

श्री कपूर चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सामनीय मंत्री महोदय ने कहा कि शाहबाद डिवीजन में बाढ़ की समस्या नहीं है। ऐसी बात नहीं है वल्कि वहां पर तो बाढ़ की समस्या बड़ी गंभीर और पुरानी है। शाहबाद के इलाके में बाढ़ की समस्या को लेकर गांव वालों में आपस में सन् 1994 में गोली भी चली थी। अध्यक्ष महोदय, 14 गांव नलवी नहर की एक तरफ पड़ते हैं और 7 गांव दूसरी तरफ पड़ते हैं। अगर नलवी नहर के बंद को बंद कर दिया जाता है तो बरसात के दिनों में इसके टूटने के कारण एक तरफ के लोगों को डूबने का डर रहता है और बंद को खोल दिया जाए तो दूसरी तरफ के लोगों को खतरा हो जाता है। इस समस्या को दूर करवाने के लिए, सरदार दीदार सिंह जी जो रजिस्ट्रार के पद से रिटायर हुए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे और मुख्य मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि दोनों तरफ का पानी निकाल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नलवी नहर के दूसरी तरफ एक पुराना बंद है और सन् 1996 में बरसात के दिनों में जब वहां पर पानी 4-4 फुट हो गया तो रात के समय उस बंद को एक तरफ से गांव वालों ने काट दिया, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे लोग डूब जाते। लेकिन बंद टूटने से दूसरी तरफ के लोगों के डूबने की आशंका हो गई और गांव वाले आपस में लड़ने के लिए इकट्ठे हो गये। जब इस बारे में डी०सी० को पता लगा तो उन्होंने वहां पर श्री रणवीर शर्मा, एस०पी० को भेजा। एस०पी० साहब मीके पर जाकर तीन ट्रैक्टर ट्राली नौजवानों को गिरफ्तार करके शाहबाद थाने में ले आए। जब इस बारे में मैने शर्मा जी से पूछा कि यह आपने क्या किया? तो शर्मा जी ने मुझे कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वहां पर गोलियां और भाले चल जाते। अध्यक्ष महोदय, मैने एस०पी० से कहा कि इन लोगों का चालान मत करना, बाद में देख लेंगे। अध्यक्ष महोदय, सारी रात वे लोग वहां जेल में रहे। अगले दिन सुबह उस इलाके के 500-600 आदमी मेरे पास रैस्ट हाउस में आ गये। उस इलाके में कुमाऊ विरादरी के लोग रहते हैं। वे लोग वहां रैस्ट हाऊस में शाम तक बैठे रहे और जब शाम को पानी पर कंट्रोल हो गया उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, तब वे लोग वहां से गये। अध्यक्ष महोदय, वह नाका उस समय खोला था लेकिन आज तक वह नाका बंद नहीं हुआ है, उस एरिया के लोग उस नाके को बंद नहीं होने देते। लेकिन अगले गांव वाले कहते हैं कि अगर यह बंद नहीं किया गया तो उनके वहां बाढ़ आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वहां का पानी हर साल एस०वाई०एल० में काटकर डाला जाता है। पहले पाईप लगाई गई लेकिन पाईपों से यह पानी नहीं निकलता, इस बार दूसरे तरीके से यह पानी निकाला गया था। अध्यक्ष महोदय, अगर पंजाब से एस०वाई०एल० में पानी ज्यादा आ जाता है तब हमारे वहां का पानी एस०वाई०एल० में नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों की यह समस्या बहुत गंभीर और पुरानी है। नी-गजे पीर से पानी रावा, रंडी, दाऊमाजरा, गोरीपुर, बोरीपुर, कल्याणा, मददीपुर, फोंककर, नहारमाजरा, कलसाणी, ममुमाजरा और सैनी माजरा से होता हुआ जाता है। और नलवी के दूसरी तरफ पानी वसंतपुर, बीजपुर, मधेड़ी, अजराकर और शंति नगर से होता हुआ जाता है। अध्यक्ष महोदय, नलवी नहर का जो पुराना बंद है वह तीन साल से टूटा हुआ है। एक तरफ के लोग तो कहते हैं कि यह बंद, बंद होना चाहिए और दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि यह खुला रहना चाहिए। यह समस्या वहां के लोगों की है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों की यह समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जिस इलाके की समस्या वैद्य कपूर चंद जी ने बताई है वह मारकण्डा नदी का इलाका है और जब भारी वर्षा होती है तब मारकण्डा नदी का लेवल उस इलाके की जमीन से ऊपर हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब मारकण्डा नदी का पानी का लेवल नीचे हो जाता है तब उस इलाके का पानी निकल पाता है। आदर्शणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 जनवरी, 1999 का एक मीटिंग हुई थी और उसमें जितनी भी बाढ़ से संबंधित परियोजनाएं थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी

हों, सारे हरियाणा के लिए जो भी परियोजनाएं मंजूर हुई हैं उनमें से तीन परियोजनाएं इस इलाके की समस्या के लिए ही मंजूर की गई हैं और वे हैं— झांसा के ऊपरी स्तरीय बांधों और बांध की बुर्जी नम्बर 4500 से 10000 के साथ - ड्रेन का निर्माण करना। शाहबाद तहसील के लांडी दाऊ माजरा/बजीदपुर तथा केसरी गांव की कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए लांडी ड्रेन बुर्जी नम्बर 07500 का निर्माण करना। उसका वित्तिका की बुर्जी नम्बर 23800 पर साइफन लगाकर शाहबाद तहसील के ढोल बबकपुर तथा गोरखा इत्यादि गांवों की कृषि भूमि का बचाव करना। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री कपूर चन्द शर्मा ने बताया कि वहाँ पिछले कई सालों की समस्या है, यह ठीक है और उसके लिए पहले चौधरी बंसी लाल जी के समय में एक स्कीम बनी थी कि इस मारकण्डा नदी के अप-स्ट्रीम पर एक बैराज बनाया जाए और वह स्कीम बन गई थी। उस स्कीम का एक तो यह फायदा था कि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी होती और दूसरा फायदा यह था कि मारकण्डा नदी का पानी एक साथ नीचे नहीं आता तो यह इलाका भारी वर्षा होने पर बाढ़ से भी बचता। लेकिन सी०डब्ल्यू०सी० ने वह स्कीम इस वजह से नामंजूर कर दी थी कि नदी के अप-स्ट्रीम में ज्यादा सिल्टिंग होगी और ज्यादा सिल्टिंग होने की वजह से वह बैराज एक-दो साल में बेकार हो जाता। इसलिए वह स्कीम लागू हो नहीं पाई थी। फिर भी इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय हो तो श्री कपूर चन्द शर्मा जी जैसी सलाह देंगे, वैसे कर देंगे।

श्री कपूर चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मारकण्डा नदी के पानी का सवाल नहीं है और इससे यह बाढ़ नहीं आती है। शाहपुर के पास, मोड़ी के पास और नौ गजे पीर के पास जो नाले हैं, यह पानी वहीं से उछल कर जाता है और इन सभी गांवों में जाता है और नालियों में टक्कर खाता है। वहाँ बन्द बना हुआ था जो कि बहुत पुराना है और काट दिया है। लेकिन बन्द से परली साइड में एक जनसुई हैड में उन्होंने ड्रेन डाली हुई थी जो कि बन्द हो चुकी है। जब नलवी से बन्द के साथ-साथ जनसुई हैड में पानी डाल दें तभी कुछ बात बन पायेगी। अध्यक्ष महोदय, पहले हमने एक स्कीम बनाई थी कि जी०टी० रोड और रेलवे रोड के बीच में से पानी मारकण्डा नदी में डाल दें लेकिन रेलवे वालों ने मंजूरी नहीं दी। अब जी०टी० रोड से परवा की साइड में ड्रेन निकाल कर मारकण्डा नदी में डाल दें और वहाँ गेट लगा दें तो वह पानी मारकण्डा में आ सकता है और उधर जनसुई हैड में आ सकता है तभी ये सारा इलाका बच सकता है। अतः यह मारकण्डा नदी की बाढ़ का सवाल नहीं है यह पानी तो ऊपर से आता है जो शाहपुर का, मोड़ी का और नौ गजे पीर का है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बारे में कोई विचार करेंगे।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, वहरवाल, मारकण्डा पर गेट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि गेट लगाने का नुकसान ही होगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाढ़र लैवल अपने आप रात के समय नीचे हो गया तो जो पानी का नैचुरल फ्लो है उसके हिसाब से पानी अपने आप ही चला जाता है और जैसा श्री कपूर चन्द शर्मा जी बता रहे हैं कि मारकण्डा नदी के पानी का कोई संबंध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस इलाके का पानी मारकण्डा नदी में ही जाता है और जब मारकण्डा नदी का पानी का लैवल अपने आप बाहर से ऊंचा हो तो वह पानी खड़ा हो जाता है और ज्यों-ज्यों मारकण्डा नदी का पानी नीचे जाता है तो वह पानी अपने आप नैचुरल फ्लो से निकल जाता है। यह कोई 10 दिन या बीस दिन या महीना भर तक पानी नहीं भरता। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पानी भरता है और अब मारकण्डा नदी का लैवल नीचे चला जाता है तो वह पानी नैचुरल फ्लो से निकल जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस इलाके में जब नेशनल हाई वे बना तो उस समय वहाँ पर त्रिज के अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ समस्या आई थी। त्रिज की कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर पानी रुक गया था लेकिन

[श्री हर्ष कुमार]

वह पानी भी तीन चार दिन के अन्दर ही निकाल दिया गया था। इसके अलावा माननीय सदस्य की कोई और समस्या हो तो वह बताएं।

श्री कपूर चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपने महकमे के इंजीनियर वहां भेज कर सर्वे कराया लें और वे उस वारे में कोई सुझाव दें उसके हिसाब से कर दें।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं महकमे के इंजीनियर वैद्य जी के पास भेज दूंगा। वैद्य जी उनको जो सुझाव देंगे उसके हिसाब से वे स्कीम बना देंगे। हम इनकी समस्या का हल जरूर करवाएंगे।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में थर्मल पावर प्लांट पानीपत है उस थर्मल पावर प्लांट में पानी यूज होने के बाद जो पानी वहां से निकलता है उस पानी में थर्मल पावर प्लांट की राख मिक्स हो कर सुताना गांव की अढ़ाई सौ एकड़ जमीन में जाती है उस पानी के कारण उस गांव की जमीन में सेम आ गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उस पानी को कोई ड्रेन बनाकर प्रीपर ड्रग से निकलवाने का प्रबंध करवाएगी ताकि उस गांव को सेम की समस्या से बचाया जा सके।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद वहां मौके पर गया था। मैंने वहां पर देखा था कि लोग थर्मल पावर प्लांट के पानी से अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। जब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है तो वह पानी जरूर लोहारी गांव की 50-60 एकड़ जमीन में से होते हुए थर्मल पावर प्लांट में ड्रेन निकाली हुई है उसमें से होकर आगे निकल जाता है।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी वहां मौके पर गये थे, यह बात सही है लेकिन उस पानी से सुताना गांव की 200-250 एकड़ जमीन खराब हो गई है और उस जमीन में सेम की समस्या पैदा हो गई है। उस पानी को ड्रेन बना कर ड्रेन के माध्यम से यूज किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या वह पानी खेती के काबिल है या नहीं।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर मौके पर देख कर आया हूँ। किसान उस पानी से अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। थर्मल पावर प्लांट वालों ने जो ड्रेन बनाई हुई है उस ड्रेन से वह पानी आगे जाता है। जो राख होती है वह उन्होंने जो पौड बनाया हुआ है उसके अंदर नीचे बैठ जाती है पानी बाकायदा बितर कर आगे जाता है। वह पानी बाकायदा खेती के लिए काबिल है। फसल को उस पानी से कोई नुकसान नहीं होता है।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि शुरु-शुरु में उस पानी से किसान सिंचाई कर लेते थे लेकिन अब उस पानी के कारण सुताना, जाटल और लोहारी गांवों की डेढ़ सौ एकड़ जमीन खराब हो गई है। इन गांवों में उस पानी से बड़ी भारी समस्या है। सच्चाई यह है कि उस पानी से सिंचाई नहीं हो रही है। इन गांवों की लगभग डेढ़ सौ एकड़ जमीन में पिछले कई सालों से किसी भी फसल की बिजाई नहीं हुई है। वहां पर 150 एकड़ जमीन ही नहीं बल्कि 500-600 एकड़ जमीन खराब हो चुकी है। उस पानी को निकालने के लिए जो ड्रेन बनाई गई थी उसकी सफाई न होने की वजह से उसके अन्दर से हो कर पानी नहीं चल सकता है। इसके अलावा जाटल गांव के पास से जो वादशाह ड्रेन निकलती थी उस ड्रेन को लोगों ने बंद करके उसके ऊपर बिजाई करनी शुरु कर दी है। इस वारे में हम कई बार महकमे को कह चुके हैं, दरखास्त दे चुके हैं। इसके अलावा जो लोहारी की तरफ ड्रेन जाती है जब तक उसकी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो जाती, तब तक वहां के किसानों का बुरा हाल

रहेगा। उसकी सफाई के लिए वहां के किसान बहुत दिनों से परेशान हैं। मंत्री जी उस पानी में सिंचाई की बात कहते हैं वह तो बहुत पुरानी बात है, वह तो शायद 10 साल पहले की बात है। अब वे बिजुई क्या करेंगे क्योंकि उनकी सारी जमीन सेम में आ गई। जितना भी आस-पास का इलाका है जिसमें तकरीबन 150-200 एकड़ जमीन आती है, वह खराब है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर मेरा भी 70 एकड़ का फार्म है। वह सारा का सारा खराब होता जा रहा है। अब वहां पर 5 फुट पर चौंवा आ गया है। वहां पर बिजुई के लिए प्रोब्लम आ जायेगी इसलिए आप इस बारे में गहराई से सोचें और जो सेम वहां पर बड़ा रही है उसको खल करवायें। सेम के प्रभाव से बचने के लिए वहां से जो ड्रेन जाती है उसकी सफाई होनी सबसे पहले जरूरी है। जब हम आपके महकमे के आदमियों को कहते हैं कि ड्रेन की खुदाई करवा दें तो वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम ड्रेन की खुदाई करवा देते हैं। फिर बरसात का समय आ जाता है। तब वे चार देलदार भेज देते हैं और कह देते हैं कि हमने सफाई कर दी, इसलिये आपसे प्रार्थना है कि वहां का मामला बहुत सीरियस है इसलिए इस को आप सीरियसली लें ताकि वहां की जमीन का बहुत बुरा हाल न हो। इसलिए मेरी धरखास्त है कि आप अपने महकमे को कह करके इसको दिखाकर कोई हल निकालें। आपकी मेहरबानी है कि आप वहां की समस्या को देख करके आये हैं।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों साधियों को साथ ले जाकर के और अपने इंजीनियर को साथ ले आकर के उसका मुआयना कर लेंगे और जो कुछ हल हो सकता होगा, जरूर करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 817

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री देवराज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 939

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रामफल कुण्डु सदन में उपस्थित नहीं थे।)

M.L.A's Local Area Development Scheme

*862. **Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to re-introduce the M.L.A's Local Area Development Scheme ?

Finance Minister (Shri Charan Dass) : No. Sir.

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूँ और इस सवाल के लिए आपके सहयोग की भी जरूरत है। जैसा अभी मेरे साथी जैन साहब बता रहे थे कि एम०पी० कोटे से दो नलकूप लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि एम०पी० कोटे से एक एम०पी० को जी 1 करोड़ रुपये मिलते थे वह राशि अब बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। हमारे साथ लगते पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में भी एम०एल०एज० का कोटा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख रुपये हो गया है। अब जिस गांव में भी गली पक्की बनती है तो वहां पर जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यह गली तो एम०पी० साहब ने बनवा दी है इसलिए अब आप यह

[श्री कैलाश चन्द्र शर्मा]

दूसरी गली बनवा दें। विकास राशि न मिलने से किसी विधायक को गांव में जाने में बड़ी भारी समस्या आने लग गई है। गांव के सारे सरपंच एम०पी०जे० के पास जाने लगे हैं। इतना ही नहीं एक एम०पी० को 30-35 गैस के कनेक्शन और टेलीफोन के कनेक्शन लोगों को देने की सुविधा मिली हुई है। मैं चाहता हूँ कि विधायकों को जो कौटा पहले मिलता था उसको पुनः चालू किया जाए। यह सभी विधायकों के लिए ठीक रहेगा। इसमें पैसा तो सरकार से ही लगना है। वह पैसा पंचायत समितियों के पास डी०सी० के माध्यम से ही जाना है। हमारा तो सिर्फ नाम होना है कि फलों गली विधायक ने बनवायी है। हमें आने वाले समय में इसका फायदा हो सकता है। जब गांव के लोग हमें किसी फंक्शन में बुला लेते हैं तो वहां पर 5-10 हजार रुपये उनको देने के लिए काम में लाये जा सकते हैं। अब गांवों में सारा श्रेय एम०पी० को ही जाता है, विधायकों को गांवों में कोई बुलाता ही नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि विधायक को यह थोड़ी भी छूट मिलनी चाहिए। हमारा पड़ोसी प्रान्त राजस्थान जिसको सबसे कम पैदावार वाला प्रान्त कहते हैं उसमें भी अपने विधायकों को मिलने वाले पैसे को पहले से डबल कर दिया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री चरण दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आनरेबल मेम्बरज को बताना चाहता हूँ कि 1995 में लोकल एरिया डिवेलपमेंट के माध्यम से एम०एल०एज० को 20 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपये देने का प्रावधान एम०पी० पैटर्न पर किया गया था। पहले साल 1219.25 लाख रुपया डी-सेंट्रलाइजेशन के तहत, 500 लाख रुपया एच०आर०डी०एफ०ए० के माध्यम से व 80.75 लाख रुपया इम्प्लीमेंट एश्योरेंस के माध्यम से एम०एल०एज० को मिला था।

श्री अध्यक्ष : क्या 1995 में सभी एम०एल०एज० को पैसा मिल गया था ?

श्री चरण दास : 20 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपया देने की पॉलिसी सभी एम०एल०एज० के लिए थी। वर्ष 1996 में यह स्कीम बन्द कर दी गई थी क्योंकि इसका तरीका ठीक नहीं था।

श्री अध्यक्ष : मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप यह बताएं कि क्या 1995 के अन्दर सभी एम०एल०एज० को यह 40 लाख या 50 लाख रुपया दिया गया था ? क्योंकि उस वक्त हम भी एम०एल०एज० थे, हमको यह पैसा नहीं मिला था।

श्री चरण दास : अध्यक्ष महोदय, जो पॉलिसी थी वह सभी के लिए थी लेकिन यह पिछली गवर्नमेंट के पार्ट पर लैप्स रही कि वह उनको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 1996-97 में पांच लाख, 1997-98 में साढ़े पांच लाख और 1998-99 में 14 लाख रुपये डी-सेंट्रलाइज किए गए और डी०सी० को भेजे गए हैं। अगर आनरेबल मेम्बरज चाहते हैं तो फॉरम जा कर उस पैसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

लोक सम्पर्क राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सेनी) : अध्यक्ष महोदय, उस सरकार के वक़्त में वह पॉलिसी तो सभी विधायकों के लिए थी, लेकिन पैसा सब के लिए नहीं था।

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी, आप कृपया यह बताएं कि 1995-96 में सभी को पैसा मिला या नहीं मिला ? क्योंकि हम भी उस वक़्त विधायक थे लेकिन हमें यह पैसा नहीं मिला था इस बारे में आपका रिकार्ड क्या कहता है ? (विद्युत्)

शिक्षा मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपने विल्कुल ठीक फरमाया। पिछली सरकार के समय में विधायक लोकल डिवैलपमेंट फंड की योजना थी और उसमें पिछली सरकार की बड़ी भेदभावपूर्ण नीति रही। किसी जिले में तो पैसा दे दिया गया और किसी जिले में नहीं दिया गया, किसी विधायक के क्षेत्र में पैसा दे दिया गया और किसी विधायक के क्षेत्र में पैसा नहीं दिया गया। माननीय साथी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा जी की समस्या ठीक है और यह सरकार इस पर विचार करेगी।

Extension of Industrial Area, Ambala Cantt.

*870. **Shri Anil Vij** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for the extension of the Industrial Area, Ambala Cantt.; and

(b) if so, the time by which the above mentioned proposal is likely to be materialised ?

उद्योग मंत्री (श्री शशि पाल मेहता) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी एक इण्डस्ट्रियल एरिया है व बहुत पुराना बना हुआ है और वहां अभी सैचुरेशन नहीं हुआ है और इण्डस्ट्रीज के एक्सपेंशन का वहां पर अभी काफी स्कोप है और लोग भी वहां पर निश्चित रूप से उद्योग लगाना चाहेंगे और लोग वहां पर इण्डस्ट्रीज लगा भी रहे हैं। वहां पर इण्डस्ट्रीज को एक्सपेंड करने का काफी स्कोप है लेकिन इसके बावजूद मन्त्री महोदय ने उत्तर 'नहीं' में दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस सब के बावजूद भी यह उत्तर 'नहीं' में क्यों है ?

श्री शशि पाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैंट से 12 किलो मीटर की दूरी पर साहा ग्रोथ सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार की स्वीकृति आ चुकी है और पचास लाख रुपये की राशि भी हमें मिल चुकी है। वहां पर 400 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके काम चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ और भी कई इण्डस्ट्रियल टाऊन हैं इसलिए अम्बाला में और इण्डस्ट्रीज का विकास करने की जरूरत नहीं है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत स्वागत योग्य बात है कि साहा ग्रोथ सेंटर का काम चालू होने वाला है। पिछले 10-12 साल से साहा ग्रोथ सेंटर फाइलों में दबा पड़ा था और वर्तमान सरकार के आने के बाद इस पर कार्यवाही आरम्भ होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि साहा ग्रोथ सेंटर पर काम कब से शुरू हो जाएगा और वहां पर कब से इण्डस्ट्रीज लगनी शुरू हो जाएंगी ?

श्री शशि पाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अपने साथी श्री अनिल विज को बताया है कि भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और 50 लाख रुपये की राशि भी आ चुकी है तथा इस पर काम भी चालू है। यह बहुत जल्दी ही विकसित होने वाला है और वहां पर लगाने के लिए पैसा भी अवेलेबल है। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस की नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि यमुना नगर, बबूवाल, वरवाला आदि भी अम्बाला कैंट के साथ ही लगते हैं जहां हमने इण्डस्ट्रीज के लिए जमीन ऐक्वायर की है और वहां पर भी काम शुरू हो रहा है। इसी तरह से मैं यह बात बताना चाहता

[श्री शशि पाल मेहता]

हूँ कि मनेसर में 1749 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। कंट्रोलों की लागत से यह ऐसा इण्डस्ट्रियल टाऊन तैयार होगा जो कि पूरे इण्डिया में नहीं है। यह टाऊन अपने आप में एक मिसाल होगा। उसकी सड़कों पर काम चालू हो गया है। इन सड़कों के निर्माण का काम हमने प्राइवेट पार्टीज को दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रीज में जो थोड़ी बहुत कमी थी, वह बिजली की वजह से थी। हमारे मुख्य मंत्री जी की मेहनत और अथक प्रयासों से वह कमी भी दूर हो जाएगी। हमारे प्रदेश में 6 महीने के अन्दर-अन्दर 24 घंटे बिजली मिलेगी। जिसके कारण हरियाणा में इण्डस्ट्रीज को और भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, भिवानी और महेन्द्रगढ़ के एरिया में भी आपका कोई इण्डस्ट्रीयल टाऊन बनाने का विचार है ? अगर है तो उस बारे में बताएं ?

श्री शशि पाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, ऐसा विचार है। इसके अलावा अगर कहीं से ऐसी डिमान्ड आएगी और वे ऐप्लीकेशन देंगे तो हम वहाँ पर जरूर इण्डस्ट्रीज लगवाएंगे।

श्री सत पाल सांघवान : अध्यक्ष महोदय, दादरी के आस-पास का एरिया जिसमें मेंडा खेड़ी व बादल आदि गांव आते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा टमाटर पैदा होते हैं। जब टमाटरों का सीजन होता है तो किसानों को उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं और वे किसान चार-पांच दिन तक दिल्ली में टमाटरों को बेचने के लिए इंतजार करते रहते हैं। क्या मंत्री महोदय, उन किसानों के लिए उन्हीं एरियाज के पास कोई ऐसा प्रबंध करेंगे ताकि उनकी उनकी उपज के उचित दाम मिल सकें ?

श्री शशि पाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का हमारे इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि ये इस बारे में हमें लिखकर दें, हम इस बारे में विचार कर लेंगे। वैसे तो यह एग्री इण्डस्ट्री का मामला है, इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपने फर्माया कि अगर कोई इण्डस्ट्रियल एप्लीकेशन लिखकर दे दे अगर ऐसा हो, तो क्या आप वहाँ पर इण्डस्ट्रियल टाऊन बनवा देंगे ?

श्री शशि पाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, महकमे के नॉर्म के मुताबिक जहाँ ऐसी जरूरत होती है वहाँ पर हम जमीन ऐक्वायर करते हैं और उस बारे में जमींदारों को नोटिस देते हैं। उसके बाद इण्डस्ट्रियल टाऊन में इण्डस्ट्रीज बनाने के लिए एप्लीकेशन मांगते हैं। इसके अलावा अगर किसी एरिया से इण्डस्ट्रियल टाऊन बनाने की डिमान्ड आती है तो उस बारे में विचार करके काम किया जा सकता है।

श्री जगदीश नेयर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि मेरा हसनपुर हलका पिछड़ा हुआ है। हसनपुर और होडल के किसान इण्डस्ट्रियल टाऊन के लिए जमीन देने को भी तैयार हैं। अगर मंत्री जी वहाँ पर इण्डस्ट्रियल टाऊन बनाने के लिए तैयार हों तो वहाँ के किसान सस्ते दामों पर जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये वहाँ पर इण्डस्ट्रियल टाऊन बनवाएंगे ?

श्री शशि पाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, पलवल के लिए इण्डस्ट्रियल टाऊन बनाने के बारे में विचार हो रहा है और इनका एरिया पलवल के नजदीक है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि गांव-गांव में इण्डस्ट्रियल टाऊन नहीं बन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

राज्यपाल से सन्देश

15.00 बजे श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गण, मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है।

“प्रिय अध्यक्ष जी,

मैं आपके अर्थ सरकारी पत्र सं० एच०बी०एस०एल०ए० 36/99/3570 दिनांक दो फरवरी, 1999 के लिए जिसके द्वारा आपने मुझे हरियाणा विधानसभा द्वारा दिनांक दो फरवरी, 1999 को पारित धन्यवाद प्रस्ताव की प्रति प्रेषित की है, आभार प्रकट करता हूँ। कृपया मेरी ओर से सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करें।”

अतः महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। (शम्पिंग)

विजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 2.15 P.M. on Friday, the 5th February, 1999 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday and Tuesday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put and on Wednesday, the 10th February, 1999 at 2.00 P.M. and adjourn after conclusion of Business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the Business on 8th February to 10th February, 1999 be transacted by the Sabha as under :—

- | | |
|---|--|
| Monday, the 8th February, 1999
(2.00 P.M.) | 1. Questions Hour.
2. Presentation and adoption of Second Report of Business Advisory Committee.
3. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1999-2000 and reply by the Finance Minister.
4. Legislative Business. |
|---|--|

[Mr. Speaker]

Tuesday, the 9th February, 1999
(2.00 P.M.)

1. Questions Hour.
2. Presentation of Assembly Committees Report.
3. Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 1998-99.
4. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 1999-2000.
5. Legislative Business.

Wednesday, the 10th February, 1999 (2.00 P.M.)

1. Questions Hour.
2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting.
3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
4. Motion under Rule 121.
5. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 1998-99.
7. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1999-2000.
8. Legislative Business.
9. Any other Business.

लोक निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने इस बारे में आदरणीय मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना की है कि वी०ए०सी० की रिपोर्ट में बुद्धवार को जो सेशन का समय दो बजे रखा गया है उसकी बजाए अगर यह प्रातः 10.00 बजे हो जाए तो यह समय सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the House will meet at 10.00 A.M. instead of 2.00 P.M. on 10th of February, 1999.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The House shall meet at 10.00 A.M. instead of 2.00 P.M. on 10th February, 1999.

Now, the Minister of State for Parliamentary Affairs will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations as amended and contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations as amended and contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations as amended and contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion as amended was carried.

वर्ष 1999-2000 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरांरम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the Budget for the year 1999-2000 will be resumed Shri Sat Pal Sangwan.

श्री सत पाल सांगवान (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, 3 फरवरी, 1999 को वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विपक्ष के भाइयों के वगैर मुझे तो सदन में जान ही नजर नहीं आती। वे गालियाँ देकर सरकार को उल्टा सीधा कहकर चले गए। आज मैं उनको सुनाना चाहता था लेकिन मेरा अहोभाग्य कि वे आए ही नहीं। विपक्ष के साथियों की अनुपस्थिति में मेरा बोलने का मन तो नहीं हो रहा लेकिन आपने बोलने के लिए समय दिया है तो बोलना ही है।

श्री अध्यक्ष : आपका अहोभाग्य बोलने का है या खाली वेंचों का है ? (हंसी)

श्री सत पाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए अपोजीशन के भाइयों का होना बहुत जरूरी था। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है, कर रहित है। उसमें हमारी जो मैन प्रोब्लम्स हैं जैसे बिजली, पानी, ऐग्रीकल्चर, रोड्स उन सबकी ओर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था तब भी यहाँ विधान सभा में बड़े कमाल हुए थे और दलबदल के लिए हरियाणा प्रसिद्ध हो गया था। उस समय एक विधायक ऐसे भी थे जो सुबह एक दल में, दोपहर को दूसरे दल में और शाम को तीसरे दल में पहुँच जाया करते थे। ऐसी बातों से हरियाणा की चारों तरफ से बदनामी हो गई थी। हरियाणा की जनता भी खबराने लगी थी कि इस प्रदेश का क्या होगा ? 1967 में चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली उस वक़्त हरियाणा में क्या हालत थी। हम लोगों के घर में जब मेहमान आते थे सिर्फ़ तख़ मापड़े बना करते थे, हम जख़ रीक़तक में पढ़ने गए तो होस्टल की किचन में हमें भुसने नहीं देते थे कि यहाँ तो मेहमानों का खाना बनेगा। ऐसे वक़्त में चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली और हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी, हर गांव में सड़कों का अरेंजमेंट किया गया। अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता है कि हमारे इलाके की जान जो लिफ़्ट इरीगेशन स्कीम थी, कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऊपर आ सकेगी, चौधरी बंसी लाल जी उसे

[श्री सतपाल संगवान]

ऊपर लाए, जिससे वहां के लोगों को बेधुमार फायदा हुआ। हमारे बुजुर्ग तो कभी सोचा भी नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हरियाणा लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए बधाई देना चाहता हूँ। एक हमारे अपोजीशन के साहब छाती खोलकर कहा करते थे कि मेरे पास इतनी प्रोपर्टी है कि एक दिन मैं फाईव स्टार होटल खड़ा कर सकता हूँ। ये बातें उन्होंने जनता में भाषण देते हुये कही हैं लेकिन अब पता लग जायेगा क्योंकि लोकायुक्त की नियुक्ति ऐसे ही राजनीतियों के लिए की गई है। इसमें मुख्य मंत्री से लेकर छोटे कर्मचारी तक जो भी दोषी होगा, उसे वरक्षा नहीं जायेगा। अब पता लग जायेगा कि एक दिन मैं फाईव स्टार होटल खड़ा करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। इनको जनता से कोई प्यार नहीं है, हरियाणा की जनता से कोई मतलब नहीं है। स्पीकर सर, ये विपक्ष के साथी लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं, आपको याद होगा कि 1989 में चुनाव में इनके नेता ने हुक्म दिया था कि कितने भी आदमी मरे लेकिन हमारा आदमी चुनाव नहीं हारना चाहिये। इन्होंने वहां एक पुलिस आफिसर को भी भेजा था लेकिन वह तो रास्ते से ही भाग गया था। स्पीकर सर, आपको याद होगा कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी के घर के सामने एक बमिये के लड़के को मार दिया था और उसकी लाश को भी वहां से उठाने नहीं दिया था और जब हमारे कुछ आदमी उस लड़के को अस्पताल में ले गये तो उसकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था और एफ०आई०आर० लौज नहीं होने दी थी। आज वे लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं। किस तरह जुई में एक लड़की को गोलियों से भून दिया गया था, इनको कुछ खोब समझ कर बात करनी चाहिये। महम में क्या हुआ था वह सब आपको याद होगा। लॉ एण्ड आर्डर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोनीपत में वस स्टैण्ड को जलाया गया और कहा कि जब तक यहाँ का धुआँ दिल्ली तक नहीं पहुँचेगा तब तक किसको पता चलेगा। उस समय टेलीफोन एक्सचेंज जलाई गयी। यह सब किसी की प्रोपर्टी थी ? यह सब हरियाणा की जनता की प्रोपर्टी थी। हरियाणा की जनता उन्हें कभी भी भाफ नहीं करेगी। यह बात मैं उनको चेलेंज के साथ कह सकता हूँ। वे यह कहा करते थे कि जब तक लोग मरेंगे नहीं, तब तक हमारा राज कैसे चलेगा। मेरी यह सब बातें वे आज सुनते तो अच्छा था। अब मैं विजली के बारे में बताना चाहता हूँ। विपक्ष के भाइयों को सबसे ज्यादा तकलीफ विजली के बारे में है। उनके दो-चार साथी कभी जब मेरे से बात करते हैं तो कहते हैं कि जब 24 घण्टे विजली लोगों को मिल जायेगी तो हम कहाँ जायेंगे, तब मैंने कहा कि तुम विजली के तार को हाथ लगा कर खड़े हो जाना। तुम्हो पता चल जायेगा कि 24 घण्टे विजली मिल रही है या नहीं ? सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन्हें विजली से ही है। उनका एक ही मतलब है कि किस तरह से चौधरी बंसी लाल जी को हरियाणा की जनता को 24 घण्टे विजली देने से रोके। क्योंकि 24 घण्टे विजली अगर हरियाणा की जनता को मिल जायेगी तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। उनका काम सिर्फ जनता को बहकाने का है वे शांति को भंग करना चाहते हैं। उनको किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से कोई मतलब नहीं है। जब विजली हरियाणा के लोगों को 24 घण्टे मिलेगी तो हरियाणा की जनता का उद्धार हो जायेगा और विपक्ष के भाई देखते रह जायेंगे (विन्) अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सड़कों की बात है, इनकी मरम्मत और अन्य नई सड़कें बनाने के लिए बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। दलाल साहब ने सड़कों का कार्य तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, लेकिन भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है। विपक्ष वाले भाई कहते थे कि भिवानी के अंदर एक ईट भी नहीं लगी है, लेकिन जब हम ने इनको बताया कि वहाँ-वहाँ पर कार्य हो रहे हैं अथवा हुए हैं, तो वे वहाँ से आंख मूंदकर निकल जाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में सड़कें बनी हैं, उनकी मरम्मत हुई है तथा और अच्छे कार्य अभी होने वाले हैं। इसके साथ-साथ हमारे राज्य राजमार्गों पर चारों तरफ कार्य चल रहा है। मैं विस्त

मंत्री महोदय को धाँधे देना चाहूंगा कि उन्होंने सड़कों के लिए बजट में अच्छा प्रावधान किया है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या की समस्या थी तथा मैंने इस संबंध में हर्ष कुमार जी व मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि यह समस्या लोहारू कैनाल की वजह से ज्यादा है। मैं हर्ष कुमार जी को यह नहर भी दिखा कर लाया हूँ। मैं तो इनका धन्यवादी हूँ कि इन्होंने इस पर तुरंत काम करवाया है। इस संबंध में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक बार मुख्य मंत्री महोदय महेन्द्रगढ़ से आ रहे थे तो मुझे वायरलेस संदेश भिजवाया गया कि मैं उनकी लोहारू चौक पर मिलूँ, मैं यह सुनकर घबरा गया कि पता नहीं कि क्या बात है? मैं वहां पर जाकर मुख्य मंत्री महोदय को मिला तथा वहीं मौके पर ही सिंचाई विभाग के आफिसरों को यह पूछकर कि इस नहर पर कार्य हेतु कितना पैसा खर्च आएगा, मुख्य मंत्री महोदय ने उसके लिए स्वीकृति दे दी। मैं उनका धन्यवादी हूँ कि आज वहां पर जोरों से कार्य चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1995 में हमारे इलाके में बाढ़ आई थी तथा उस बाढ़ से भिवानी जिले के दादरी क्षेत्र में सबसे बुरी हालत हुई थी। जय श्री गांव से तो 9 महीने तक भी बाढ़ का पानी नहीं निकल पाया था। मेरी आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री जी से प्रार्थना है कि कम से कम 1995 के दौरान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत तो करवा दें। मैं उनका धन्यवादी हूंगा। वैसे पहले ही उनकी काफ़ी तारीफ कर दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ दादरी शहर की सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। अभी स्थानीय शासन मंत्री महोदयों सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि 1995 की बाढ़ के बाद उन सड़कों की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए यह सरकार तो कुछ सोचे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मुख्य मंत्री महोदय से मिलकर एक अस्पताल टेक ओवर किया था जो 5 साल से बंद पड़ा था, उसकी आज मॉडर्न नहीं हो रही है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना है कि उसकी मॉडर्न करवाएं। (विद्युत) उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जल्दी ही अपनी बात पूरी कर लूंगा। ये विपक्ष के भाई बोलकर बड़े खुश हो रहे थे लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि हरियाणा की जनता इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों को आज तक नहीं भूलती है। हरियाणा की जनता मौजूदा सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जा रहे अच्छे कार्यों को भी भूलने वाली नहीं है, इसका प्रतिफल वह अवश्य देगी। विपक्ष के साथियों ने लोगों की क्या हालत कर दी थी, वह बात आज तक नहीं भुलाई गई है, इसलिए अब क्रांति/भ्रान्ति यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है। सुशीला जैसे कांडों को आज तक भुलाया नहीं गया है। इन्होंने लोगों को जैसे झुथाया था, उसको भी जनता नहीं भूलती है। इनके ऐसे कारनामों की वजह से ही जनता ने इनके सिर्फ 9 सदस्यों को ही चुनकर यहां भेजा है। आज प्रदेश के अंदर बड़ी राजनैतिक उथल-पुथल हो रही है। और मेरे विपक्ष के भाई बड़े आराम से बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ इस हाउस में कहता हूँ कि जब 6 महीने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में बिजली, सड़कों, नहरों और पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी तब मेरे विपक्ष के भाई हमारे नजदीक भी नहीं पहुंच सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल मंत्री महोदय का एक बार फिर धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा और कर रहित बजट पेश किया है। जयहिन्द।

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस परिभाषित सदन में वर्ष 1999-2000 का बजट अनुमान 3 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत किया था। इस बजट में जनता के ऊपर कोई भी नया

[श्री चरण दास]

कर नहीं लगाया गया है। यह एक कल्पनाकारी वजट है। समाज के हर वर्ग के हित को देखते हुए, यह वजट बनाया गया है। इस वजट से समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष के नेताओं की अहम भूमिका होती है, किन्तु इस सदन के विपक्षी दलों ने कोई रचनात्मक भूमिका अदा नहीं की। जब भी सदन की कार्यवाही चली तो विपक्षी दलों ने उसमें विघ्न डाला और हाउस छोड़कर चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, जनता अपना उम्मीदवार यही सोचकर चुनती है कि वह उनकी समस्याओं को सदन में रखेगा लेकिन मेरे विपक्ष के भाइयों ने हमें जनता की कोई भी समस्या नहीं बताई और न ही अपने विचार इस सदन में रखे। अगर मेरे विपक्ष के भाई अपने सुझाव हाउस में रखते तो सरकार उनको सुनने के लिए तैयार थी और अगर इनके सुझाव अच्छे होते तो उन्हें मानती थी। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हाउस में नहीं बोले, पता नहीं क्या कारण था उन्होंने 5 तारीख को एक प्रेस नोट जारी किया है ? जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि चालू वर्ष 1998-99 में केंद्रीय सहायता में लगभग 354 करोड़ रुपये की भारी कमी हुई है और केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में लगभग 127 करोड़ रुपये की कमी होने की संभावना है। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सरकार ने नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को तनखाह देने के लिए 8 करोड़ रुपये दिये हैं, पुलिस बल को सुदृढ़ बनाने के लिए 8.48 करोड़ रुपये दिये हैं, मोलासिज को कंट्रोल करने के लिए 7 करोड़ रुपये दिये गये हैं और स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये दिये हैं। इस तरह से सरकार को इस वर्ष कुछ अतिरिक्त खर्च करने पड़े। इन कारणों से वर्ष 1998-99 में 2260 करोड़ रुपये के अनुमोदित योजना खर्च पर पुनर्विचार करके इसको 1800 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष 1997-98 के वजट से 44 प्रतिशत अधिक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए 2300 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं, जिसके लिए निर्णय योजना आयोग के साथ अधिकारियों के स्तर पर हुई बैठक में किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि विपक्ष के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बात उठाई है कि यह वजट प्लानिंग कमीशन से मंजूर नहीं करवाया गया। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 20 जुलाई को जो वजट हमने पेश किया था उसके बारे में भी सितम्बर में प्लानिंग कमीशन से बात हुई थी। इसी तरह से इस वर्ष के वजट के बारे में भी बात कर ली जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के वजट पर हम सभी ने मंथन करके अपनी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खर्च करना है वह इस प्रकार से है कि इस वर्ष सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 581 करोड़ रुपये, बिजली के लिए 500.80 करोड़ रुपये, रोड और ब्रिज तथा एक्सपैन्शन ऑफ ट्रान्सपोर्ट सर्विसिज के लिए 390.20 करोड़ रुपये तथा एक्सपैन्शन ऑफ सोशल सर्विसिज के लिए 525.43 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त जनरल, टेक्नीकल तथा वोकेशनल एजुकेशन के लिए 206.21 करोड़ रुपये और ट्रेडिंग स्पाई तथा सेनिटेशन के लिए 63.00 करोड़ रुपये रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं एवं मेडिकल एजुकेशन के लिये 53.27 करोड़ और नगरपालिकाओं के अन्तर्गत शहरी सुधार के लिये 34 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ग्रामीण एवं विशेष क्षेत्रीय विकास के लिये 68.05 करोड़ रुपये तथा कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के विस्तार के लिये 118.08 करोड़ रुपये रखे गये हैं। उद्योग हेतु 71.39 करोड़ एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी स्कीमों के लिये 135.45 करोड़ रुपये और अन्य सेवाओं के लिये 45.05 करोड़ रुपये रखे गये हैं। मैं विस्तार से यहाँ पर प्राप्ति और खर्च बता दिये हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारा मुख्य

मंत्री चौधरी बंसी लाल जी एक डायनैमिक लीडर हैं उनके साथ तथा हमारे जो सुलझे हुये मंत्री गण हैं, उन सब के साथ बैठकर विचार-विमर्श किया और स्टेट की हालत को देखकर हर चीज को ध्यान में रखकर ही हमने आपके सामने यह बजट पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने बिजली के बारे में कहा है कि बिजली का उत्पादन कम हुआ है लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1994-95 में 7017 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई थी, जबकि हमारी सरकार ने 7123 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की है जो कि तुलनात्मक दृष्टि से 113 मिलियन यूनिट अधिक है। हमने बिजली का सुधारीकरण किया है और यह लक्ष्य लेकर चले हैं कि बिजली पूरी देंगे। इसी प्रकार से बिजली के मेगावाट बारे में सवाल किया गया मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि पिछले टाइम में 3.98 मिलियन मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ था जबकि हमारे टाइम में 4.00 मिलियन मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। जिस तरह से हमने उत्पादन बढ़ाया है उसी तरह से हर रोज औसतन 371 लाख यूनिट बिजली दे भी रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इन सब हालात को देखते हुये यह जरूरी है कि बिजली, पानी और बीज की मार्केट बनाकर किसान को दी जाये ताकि वह उत्पादन बढ़ा सके, तभी किसान खुशहाल होगा और हमारी इकोनोमी की स्पीड भी बढ़ सकेगी एवं विकास के काम नज़र आयेगे। बिजली के बारे में हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि कुल 863 मेगावाट बिजली पैदा हुई है और 1200 मेगावाट नई बिजली पैदा करने जा रहे हैं और वह फरीदाबाद में गैस पर आधारित तापीय बिजली केन्द्र से तथा पानीपत में 210 मेगावाट की इकाई को पुनः आरम्भ करने और पानीपत में ही चार इकाईयों को पुनः कार्योपयोगी बनाने से उत्पादित करने जा रहे हैं। हम समय पर बिजली पैदा करेंगे और 24 घण्टे पूरी बिजली देने का प्रयास भी करेंगे। बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 1998-99 में 511.99 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा है जिसमें से 348.06 करोड़ रुपये ऐक्स्टर्नल ऐड मिलेगी लेकिन विपक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि हमें यह बाहरी सहायता नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि इक्यू-आर०सी०पी० परियोजना के तहत हथौड़ी कुण्ड चैराज बनाने का काम तेजी से चल रहा है और उस पर 113.90 करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हैं तथा कुल 219.90 करोड़ रुपये इस पर खर्च होने हैं। उनका यह भी कहना है कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस परियोजना के पूरा होने से जो पानी की उपलब्धता की कैपेसिटी है वह 16000 क्यूसिक से बढ़कर 20000 क्यूसिक तक हो जायेगी और सीजन में हर छोर तक पानी पहुंचेगा। उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा नहर से और नरवाना शाखा से हमें पानी मिलता है और इस जल क्षमता को वहाल करने के लिये हमने पंजाब सरकार को 10.84 करोड़ रुपये दिये हैं जिसमें इस साल के 4.64 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। उसके परिणाम आने शुरू हो गये हैं। पंजाब सरकार को यह पैसा इसलिये देते हैं कि वे नहरों से गाद निकलवाते हैं, उनकी सफाई करवाते हैं जिससे कि हमें 500 क्यूसिक पानी मिल चुका है और बाकी का पूरा पानी लेने का हम प्रयास करेंगे। एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में बहुत बातें होती हैं। हमारा पूरा प्रयत्न है कि हमें एस०वाई०एल० कैनाल का पानी मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी की लिफ्ट इरीगेशन स्कीम नवाई से मंजूर हो चुकी है। उस स्कीम पर 39.06 करोड़ रुपया खर्च होना है। अगर कैनाल का कंट्रोल यू०पी० के हाथ में था। उसकी सफाई के बाद पलवल और उसके आस पास के इलाकों को पानी मिला है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र के अन्दर कौआप्रेटिव के माध्यम से किसान भाइयों को जो लोन 16 परसेंट इंटरस्ट पर दिया जाता था अब वह घटा कर 14 परसेंट कर दिया है जिससे 31 करोड़ रुपए की बचत होगी। उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री चरण दास]

सभाज कल्याण विभाग के बारे में डाक्टर कमला वर्मा जी ने विस्तार से बताया। पीने के पानी के बारे में जगन नाथ जी ने विस्तार से बताया और एजुकेशन के बारे में राम विलास शर्मा जी ने विस्तार से बताया। वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना 1576.04 करोड़ रुपये की थी और उसके बारे में ओम प्रकाश चौटाला और दूसरे विपक्ष के भाइयों ने क्रिटिसाइज़ किया था। जब जवाब देने का मौका आया तो वे हाउस से गुम पाए गए। इस तरह से 1998-99 के बजट पर विपक्ष वाले कुछ देर के लिए बोले और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। जब उनको इसका जवाब दिया गया कि कर्मचारियों के लिए 1791.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तो वे दवाइयों के बारे में बात कहने लग गए। आपने उस दिन भी देखा कि किस तरह से विपक्ष के भाई हाउस के अन्दर शोर मचाने लगे और भाड़क तोड़ने लगे। उस बात का असर हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन पर भी पड़ेगा। हम केवल इसी बजट का जवाब नहीं बल्कि आगे आने वाले दो सालों के बजट का भी जवाब देंगे। हम अपने पांच साल पूरे करेंगे। हमने जनता से जितने वायदे किए हैं, उन सबको पूरा करेंगे। (इस समय श्री अच्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड आर्डर के बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने आंकड़ों के साथ विस्तार से बताया। आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी ने भी बताया और उन्होंने यह बात मानी कि कारों की चोरियां कुछ ज्यादा हुई हैं। कारों ज्यादा चोरी होने का यह भी कारण था कि लोग अपनी कारों को सड़कों पर खड़ी करके चले जाते हैं। क्योंकि कारें ज्यादा हो गई हैं और उनको घरों में खड़ी करने के लिए जगह नहीं है इसलिए घर से बाहर खड़ी करते हैं और चोर उनको ले कर भाग जाते हैं। पुलिस ने कार चोरों को पकड़ने की कोशिश भी की है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, जब क्राइम की बात होती है तो पोलिटिकल क्राइम के बारे में ज्यादा चर्चा होती है। अध्यक्ष महोदय, प्रोपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, ओल्ड एनिमिटी इस तरह के कई कारण हैं, जिन्से क्राइम हो जाते हैं। हमारे ओफिसर्स को उन क्राइम्स को सोल्व करने के लिए एक थ्यूरी बना कर चलना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहे जिसका मर्जी सख्त कानून बना दें जब तक उसके बारे में जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि प्रदेश की पर कैपिटा इंकम घटती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि स्थिर मूल्यों पर वर्ष 1995-96 के मुकाबले 1997-98 में प्रति व्यक्ति आय में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक बात ओम प्रकाश चौटाला जी ने और कही कि भ्रष्टाचार की वजह से कॉर्पोरेट टैक्स कम हुए हैं। पता नहीं वे कहां से पढ़ कर आते हैं कहां से नहीं? एक अप्रैल से दिसम्बर तक 1383 करोड़ रुपये खजाने में आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल इस समय तक 1337 करोड़ रुपये खजाने में थे। इस मद में भी वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में बैठने के बाद सत्ता पक्ष में बैठने की लालसा हर कोई करता है लेकिन फ्रस्ट्रेशन के अन्दर ऐसी बात करना, जैसी उन विपक्ष के साथियों ने की, शोभा नहीं देता। कांग्रेस के भी साथी अच्छे सुझाव दे सकते थे। हम सभी बैठकर अपने साथियों के सुझाव सुभते ताकि सरकार को भी पता लग सके कि कहां पर क्या काम होना है। अच्छे सुझाव आएंगे तो उससे स्टेट का लाभ होगा। कुछ साथियों ने बजट पर अपने सुझाव दिए और इस बजट की सराहना भी की। इन्फ्रास्ट्रक्चर और विजली के बारे में अपने अपने हल्कों से संबंधित जो सुझाव हमारे भावनीय सदस्यों ने दिए हैं, उन पर हम योजना बजट के समय विचार कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों का यह आरोप गलत है कि हम उनके साथ भेदभाव रखते हैं। कोई भी पॉलिसी सारी स्टेट के लिए बनती है किसी पार्टिकुलर कांस्टीच्युएन्सी के लिए नहीं।

बनती। विपक्ष के भाई भले ही हाउस में नहीं बैठे हैं, फिर भी, यदि वे लिख कर हमें कोई सुझाव देंगे तो हम उनके सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे। हमारी स्टेट की हालत दूसरी स्टेटों से फार बैटर है। हमारी स्टेट डिवैलपिंग स्टेट है। जब कोई स्टेट डिवैलपिंग स्टेट पर होती है तो उसे विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार प्रवन्ध कर रही है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर कोई भी सरकार आ जाए, कृषि का विरोध नहीं कर सकती। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जब हमारी कृषि की पैदावार पहले से दुगुनी हो जायेगी तो लोग अपने मकान भी अच्छे बनायेंगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएंगे, अच्छे उद्योग यहां पर लगेंगे। परिणामस्वरूप बेरोजगार व्यवृधकों को रोजगार भी मिलेगा।

स्पीकर साहब, हर विधायक ने अपनी योग्यतानुसार यहां पर विचार रखे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। अन्त में मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सदन में वर्ष 1999-2000 के जो बजट अनुमान पेश किए गए हैं उनका अनुमोदन किया जाये। धन्यवाद।

विल्ल—

(i) दि पंजाव विलेज कॉमन लैण्डज (रैगुलेशन) हरियाणा अमेंडमेंट बिल, 1999

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir I, beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1999.

Sir, I also move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once:

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Public Relations will move that the Bill be passed.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा लोक पाल (अमेंडमेंट) बिल, 1999

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will introduce the Haryana Lokpal (Amendment) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to introduce the Haryana Lokpal (Amendment) Bill, 1999.

Sir, I also move—

That the Haryana Lokpal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Lokpal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Lokpal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title**Mr. Speaker :** Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.**Chief Minister (Shri Bansi Lal) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि पंजाब ऐक्साइज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1999

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1999, and he will also move the motion for its consideration.**Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) :** Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1999. Sir, I also move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the House will consider the Bill clause by clause.**Clause 2****Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि फंजाब वेयर हाउसिज (हसियाणा अर्मेडमेंट) बिल, 1999

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will introduce the Punjab Warehouses (Haryana Amendment) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Warehouses (Haryana Amendment) Bill, 1999 .

Sir, I also move—

That the Punjab Warehouses (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Warehouses (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once

लोक निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पंजाब भाण्डागार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1999 लाने हेतु धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको भी विदित है कि यह मांग पिछले काफी समय से लम्बित थी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के किसान जब इन भाण्डागारों में अपना उत्पादन रखने जाते थे तो उनकी कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। किसान को किसी भी समय जब धन की जरूरत पड़ जाती थी तो उसके लिए इन भाण्डागारों में कोई प्रावधान नहीं था। यह पहली बार हुआ है जो किसान अपना उत्पादन भाण्डागारों में जमा करवाएंगे उनकी उत्पादन का 75 प्रतिशत लोन मिल सकेगा। हरियाणा के किसानों को पहली बार यह बहुत ही अच्छी सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए मैं एक बार फिर चौधरी बंसी लाल जी का धन्यवाद करता हूँ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Warehouses (Haryana amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting formula be the Enacting formula of the

Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) गुरु जम्बेश्वर युनिवर्सिटी हिसार (अमेंडमेंट) बिल, 1999

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Guru Jambheshwar University, Hisar (Amendment) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुरु जम्बेश्वर युनिवर्सिटी, हिसार (संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि—

गुरु जम्बेश्वर युनिवर्सिटी, हिसार (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Guru Jambheshwar University, Hisar (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Guru Jambheshwar University, Hisar (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6**Mr. Speaker :** Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 1****Mr. Speaker :** Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—
कि विधेयक पारित किया जाये।**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Bill be passed.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी की आज्ञावर्षण थी कि इस तरह से पुनिवर्सिटी का बिल होना चाहिए, इसलिए राष्ट्रपति जी की आज्ञावर्षण की लाईट में हम यह बिल लाए हैं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M., tomorrow.***3.56**

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday, the 9th February, 1999)